

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2049
उत्तर देने की तारीख : 19/12/2022

सरकारी और निजी विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थान

†2049. श्रीमती अपरूपा पोद्दार:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके संघटक कॉलेजों और विभिन्न विधाओं में सीटों की संख्या कितनी है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान शिक्षा की सभी विधाओं में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय-वार और वर्ष-वार संख्याकितनी है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले शिक्षित युवाओं की देश-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी नौकरी पाने वाले शिक्षित युवाओं की विभाग-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
- (ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नौकरी पाने वाले शिक्षित युवाओं की पीएसयू- वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
- (च) शिक्षा प्रणाली को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए सरकार की भावी योजनाओं/नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार रिपोर्ट किए गए राज्य-वार नामांकन के साथ-साथ सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का राज्य-वार विवरण https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ख) एआईएसएचई 2016-17 से 2020-21 (अनंतिम) के अनुसार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्टैंड अलोन सेस्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीएचडी, प्रमाणपत्र, एकीकृत में पास आउट का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	पीएच. डी.	एम.फिल.	स्नातकोत्तर	अवर स्नातक	पीजी डिप्लोमा	डिप्लोमा	प्रमाण-पत्र	एकीकृत	सकल योग
2016-17	28779	26325	1477919	6456386	129032	740561	67933	26151	8953086
2017-18	34400	28059	1504403	6419639	143176	737077	75383	26409	8968546
2018-19	40813	25787	1500064	6474715	159697	783914	75358	31550	9091898
2019-20	38986	18220	1577704	6650071	189608	807330	80927	39064	9401910
2020-21	25550	9897	1483828	6909846	131170	848050	85292	47403	9541036

(ग) से(ड) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा विदेश या सरकारी नौकरी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी पाने वाले शिक्षित युवाओं की संख्या का डेटा संकलित नहीं किया जाता है।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की आवश्यकताओं के अनुसार रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने पहले ही सभी मंत्रालयों/विभागों को खाली पदों को भरने के लिए समय पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की रिपोर्ट अनुसार, यूपीएससी और एसएससी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 28,838 और 2,26,845 है। चालू वर्ष के दौरान, यानी अप्रैल, 2022 से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि द्वारा लगभग 1.47 लाख नव नियुक्त को रखा गया है।

(च) युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में परिकल्पना की गई है कि एक समग्र शिक्षा के भाग के रूप में, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ इंटरनशिप करने के अलावा उनके स्वयं के या अन्य एचईआई/अनुसंधान संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ अनुसंधान इंटरनशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने अधिगम के व्यावहारिक पक्ष से जुड़ सकें और परिणामतः अपनी रोजगार क्षमता में सुधार कर सकें। एचईआई स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों, प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों और अधिक से अधिक उद्योग-अकादमिक संबंधों की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा को अवसर मिलेंगे। नीति में यह परिकल्पना की गई है कि व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा पेशकशों में एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक स्कूल आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ भी सहयोग करेंगे।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने मौजूदा पाठ्यचर्या में सुधार किया है और इंजीनियरिंग और पीजीडीएम/एमबीए पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यचर्या को लॉन्च किया है। भारतीय तकनीकी शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने और अपने छात्रों के लिए व्यावहारिक एम्पोजर सुनिश्चित करने के लिए एआईसीटीई नई इंटरनशिप नीति लेकर आया है जो पूरे भारत में तकनीकी संस्थानों हेतु पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में इंटरनशिप को अनिवार्य बनाती है।